लद्दाख सीमा भारत की नई चुनौती

http://rashtriyasahara.samaylive.com/epapermain.aspx dated 17 Aug 2013

भारत वह रणनीतिक उपाय करे जो अक्साई चीन से लगी सीमा पर उसके हितों को सुरक्षित करेगा, क्षेत्र का विकास करे और चीन के साथ सैन्य टकराव को भरसक टाले। पहला, भारत को सीमांत क्षेत्रों में अपनी तकनीकी खुफिया क्षमता को बढ़ाना है ताकि वह उस पार होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रख सके। यह वहां कैमरा स्थापित करने से बेहतर होगा, जिसे उठा लिये जाने का खतरा है

बिजॉय दाश रिसर्च एसोसिएट, आईडीएसए, नई दिल्ली

अगर काराकोरम र्दे को कश्मीर की मध्य-उत्तर सीमा और लद्दाख की दक्षिण-पूर्व सीमा में स्थित डेमचक से जोड़ने वाली कोई रेखा खिंची जाए तो हम उत्तरी-पश्चिमी लद्दाख का विशाल भू-भाग पा लेते हैं जो कि सुंदर और समस्याकारी है। यही वह इलाका है, जो चीनी सेना की "घुसपैठ" की वजह से हालिया खबरों में रहा है। चीनी घुसपैठ और भू-भाग पर उसके लगातार दावे अब भारत की सुरक्षा की नई चुनौती बन रहे हैं। मैं अपने आलेख में, विवादित क्षेत्र उत्तर-पूर्व लद्दाख, जिसमें अक्साई चीन शामिल है, में चीन की तरफ से उठनेवाली चुनौती की प्रकृति के बारे में चर्चा करूंगा। पहला, यह आवश्यक है कि विवाद के बारे में एक स्पष्ट बुनियादी समझदारी बना ली जाए। पूर्वोत्तर का यह क्षेत्र काराकोरम दर्रा और डेमचक के बीच खिंची मोटा-मोटी सीमा रेखा के अंतर्गत आता है, जिस पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। दोनों देश आज तक किसी भी सीमा रेखा पर सहमत नहीं हो पाए हैं, जो किसी भूभाग को शक्ल देता है और शांति बनाये रखता है। ऐसे किसी समझौते के अभाव में दोनों देश उस रेखा तक, जिसे वास्तविक सीमा रेखा (एलओसी) कहते हैं, सैन्य नियंतण्रका दावा करते हैं। फिर वहां दो एलएसी है : भारत का एलएसी उत्तर की ओर सीमा तक है, जैसा कि भारत के प्रकाशित नक्शे में है, जिसका उत्तरी-पूर्वी छोर, चीन के सामरिक महत्त्व का राष्ट्रीय उच्च पथ 219, जो सिंनचियांग और तिब्बत को जोड़ता है, समेत चीन के नियंतण्रमें है। वहीं चीन का एलएसी सुदूर दक्षिण तक है, जिसके अंतर्गत भारत की रिहाइशी आबादी और सैन्य व नागरिक प्रतिष्ठान आते हैं। लिहाजा, इस मसले पर कोई राय पुख्ता करने के पहले सरजमीनी वास्तविकता की जटिलता और बेतुकेपन को अवश्य ही समझना होगा। कुछ चीनी आज तक उन डेमोचक के दक्षिणी इलाके पर अपना दावा ठोकता है जो न्योमा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यह प्रखंड लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के लेह जिले में पड़ता है। इसलिए जब भारत और चीन की सेना जब समान भूभाग पर दावा करती हुई गश्त करती है, तो लाजिमी है कि आमना-सामना होती हैं। फिर द्विपक्षीय सहमति से बनी बातचीत के नियम का पालन होता है ताकि परिस्थिति सैन्य टकरावों में न बदल जाए। इसलिए दोनों गश्ती दल अपने हथियारों से जमीन की तरफ इशारा कर, चारों ओर घूमते हुए उस जगह से लौट आते हैं। यद्यपि हाल के वर्षो में, चीन की आधारभूत संरचना के विकास-जिसने सीमा-क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की गतिविधियों को आसान बना कर खूब फायदा पहुंचाया है-

भारतीय सेना और नागरिक प्रशासनकर्मियों के विरुद्ध पीएलए के चीनी भूभाग के बारे में दावे और अंततः भारत का आर्थिक, सैन्य और प्रशासनिक रूप से अपनी हैसियत मजबूत करने के फैसले के साथ क्षेत्र में स्थिति बदली है। सामारिक महत्त्व के स्थानों; मसलन, दौलत बेग ओल्डी और न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का भारत द्वारा तेजी से पुनर्नवीकरण करने, साथ ही क्षेत्र में अन्य सामाजिक-आर्थिक परियोजनाएं और सेना तैनात किये जाने की योजना से चीन हक्का-बक्का रह गया है। उसे यह डर सताता है कि इन सबसे संतुलन भारत के पक्ष में झुकेगा और इसलिए उसने पीएलए को आदेश दे रखा है कि भारत द्वारा किए जाने वाले ऐसे किसी भी विकास में अड़ंगा डाले। इसी वजह से हम देखते हैं कि चीनी सेना का दक्षिण के इलाके में अधिकार जताना लगातार बढ़ रहा है, वह गश्त कर रही है, हमारे निजी नागरिक विकास कायरे का ध्वंस कर रही है और उसमें अड़ंगा लगा रही है, परम्परागत चरागाहों से चरवाहों को खदेड़ दे रही है और ऐसे ही अनेक काम कर रही है। पीएलए के ये तमाम दांव-पेच भारत के सैन्य और आधारभूत संरचना विकास से इस क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदल जाने के पहले विवादित क्षेत्र की यथास्थिति बदलने का लाभ उठाने के लिए है। देप्सांग बल्ज में तीन हफ्ते तक पीएलए के जवानों का कैम्प लगाना ऐसी ही किंतु बेचैन कार्रवाई है।

चीन की सामरिक योजनाओं के तीन क्षेत्र

यद्यपि चीन उस क्षेत्र में इसी तरह के और रणनीतिक उपाय कुछ सामारिक योजनाओं के तहत भी करता है। ये दो और तीन क्षेत्रों में हैं : पहला, चीन अपनी सैन्य क्षमता को उस हद तक ले जा रहा है, जहां देस्पांग जैसी खास सैन्य कार्रवाई पर अगर उसके विरुद्ध भारत सैन्य कार्रवाई करे तो उसका जवाब दिया जा सके। इसलिए पीएलए सेना और वायुसेना तिब्बत क्षेत्र में अपने सैन्य अभ्यास को बढ़ा रहे हैं। यहां यह बताना पाठकों के हित में होगा कि तिब्बत को ध्यान में रख कर पीएलए का सालाना सैन्य अभियान योजना ही है। वह भारत को साफ-साफ बताता है कि चीन हिमालयी क्षेत्र में जंग के लिए हमेशा तैयार है। इस साल पीएलए ने छन्गतू सैन्य क्षेत्र नियंतण्रमें भिन्न-भिन्न तरह के तीन युद्धाभ्यास किये। इनमें पहला अप्रैल-मई में तिब्बत के पठार में सैन्य जमावड़ा और वायु सुरक्षा को देखना था। इस सैन्य अभ्यास में 1500 सैनिकों को पूर्वी प्रांत सिछुआन से तिब्बत लाकर और इसके वायु क्षेत्र को दुश्मन के हवाई हमले के मद्देनजर चाक-चौबंद कर किया गया था। इसके बाद पीएलए-वायु सेना ने हवा से जमीन पर मार करने वाला युद्धभ्यास चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान जे-11 के साथ किया था। यह रूसी लड़ाकू विमान सुज-27 का चीनी संस्करण है। तीसरा युद्धाभ्यास तिब्बत की ऊंचे अक्षांक्ष पर वास्तविक जमीनी परिस्थितियों में पीएलए आर्टिलरी इकाई की मारक क्षमता को जांचना और उसमें बदलाव लाना था। यद्यपि ये सभी युद्धाभ्यास रणनीतिक थे लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चीन तिब्बत में स्थानीय युद्ध की आसन्न परिस्थितियों के लिहाज से निरंतर अपनी सैन्य प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार कर रहा है। दूसरा क्षेत्र मीडिया है, जो चीन सरकार का भोंपू है। देस्पांग की घटना यह दर्शाती है कि क्षेत्र की यथास्थिति को बलात बदलने वाली चीनी सेना की कार्रवाई की स्वतंत्र रिपोर्टिंग को मीडिया ने किस तरह जानबूझकर उपेक्षा की। अगर ऐसा होता तो चीन को अंतरराष्ट्रीय समर्थन कम हो जाता। उस पूरे तीन

हफ्ते की तनातनी के दौरान मीडिया इस मसले पर "धुर दक्षिणपंथी" प्रतिक्रिया पर व्यंग्य और उसकी आलोचना के साथ यही बताता रहा कि भारतीय मीडिया में क्या चल रहा है। चीनी सेना के देस्पांग से तंबू उखाड़ लेने के बाद चीनी मीडिया धीरे-धीरे चीनी रणनीतिकारों, पूर्व राजनयिकों की टिप्पणियों और यहां तक कि पूर्व उप विदेश मंत्री के बयानों को प्रसारित करने लगा; जिनमें अपनी तरफ से उकसावे की कार्रवाई के स्वीकार का भाव नहीं था कि बल्कि यह सद्भावना दर्शायी गई थी कि देस्पांग में मामला शांतिपूर्ण निबट गया। हालांकि एक टिप्पणीकार ने देस्पांग में कैम्प कर रहे पीएलए सैनिकों के विरुद्ध भारत की किसी भी सैन्य प्रतिक्रिया को रोंगटे खड़े करने वाला बताया, जबकि पीएलए के एक मौजूदा अफसर और सैन्य विज्ञान अकादमी के सैन्य मामलों के विशेषज्ञ कहते रहे कि समूचा लद्दाख चीन के लिए सांस्कृति, धार्मिक और भाषागत कारणों से चीनी सीमा के दायरे में होना चाहिए। देप्सांग में पीएलए की कार्रवाई लद्दाख सीमा क्षेत्र में भारतीय सैनिकों के जमावड़े और आधारभूत संरचना के विकास की भारत की "नई अग्रिम नीति" के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। तीसरा क्षेत्र निश्चित रूप से सरकार के प्रचार से संबंधित है। चीनी सरकार वहां दो भिन्न एलएसी होने की बात नहीं मानती। न वहां वास्तविक जटिल सरजमीनी हालात के बारे में मीडिया को और लोगों को जानकारी देने के लिए हमारी तरह प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) है। चीनी सरकार लगातार कहती रही है कि उसकी सेना ने (चीनी) एलएसी का उल्लंघन नहीं किया। इसके आगे बढ़कर वह भारतीय मीडिया में छपने वाली खबरों की निगरानी करती रही, जिसमें भारतीय सेना के एक संभवत: रिटायर अफसर को यह कहते उल्लेख किया गया था कि भारत की सेना भी चीनी भूभाग में गश्त लगाती है। बस इसी बात को चीन के सरकार निर्देशित मीडिया ने उड़ा दिया कि चीनी सैनिक तो एलएसी के दायरे में रहते हैं जबकि भारतीय सैनिक उसका उल्लंघन करते हैं। अक्साई चीन अलावा चीन भारत के समूचे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता रहा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में मौजूदा स्थिति में कोई परिवर्तन 2005 में हुए समझौते के तहत असंभव है और उसमें भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया हुआ है कि सीमा समझौते की किसी भी सूरत में आबादी जस की तस रहेगी। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश भारतीय राष्ट्र राज्य का पूरी तरह से कामकाजी राज्य है और उसकी सीमा तुलनात्मक रूप से बेहतर सुरक्षित भी है। उपरोक्त विवेच्य तीनों क्षेत्र चीन का सैन्य रुख है, जो दीर्घकालीन रूप में भारत के लिए अहम रखता है। इस तरह का रुख वास्तव में धमकी भरा है। चीन का विश्वास है कि आज के हालात में व्यापक स्तर पर युद्ध की संभावना कम है। स्थानीय टकराव की संभावनाएं हैं, जो खतरे का रूप ले सकती हैं। अत: चीन सेना इन खतरों का शमन करने के लिए अपने संसाधन पर फोकस कर रही है, जिसमें भारत और चीन के बीच विवादित सीमा भी शामिल है। याद रखें कि भारत और चीन ने 1993,1996, और 2005 में समझौता किया हुआ है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दोनों पक्षों एक दूसरे के विरुद्ध और कि सीमा सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेगा और कि सीमा क्षेत्रों में होने वाले युद्धाभ्यासों के दौरान भी दोनों देशों की सेना एक दूसरे के रणनीतिक रूप से निशाना नहीं बनाएंगी। यद्यपि हालांकि इन शांति बनाए रखने की खातिर किए गए संधि-समझौतों के बावजूद चीन ने न केवल स्थानिक स्तर पर बल्कि हिमालयी क्षेत्र के आसपास में टकराव के खतरे के आकलन के लिए सैन्य अभ्यास कर और क्षेत्र में कायम यथास्थिति को बदलने की कोशिश, सच में उन दस्तावेजों के विरुद्ध है।

कई देशों से झगड़ा है उसका

हालांकि चीन अकेले भारत के विरुद्ध ही अपना दखल नहीं जताया है। उसने पूर्वी चीन सागर में जापान के खिलाफ; इसी तरह वियतनाम के साथ और फिलिपींस के साथ किया है, जिसका दक्षिणी चीनी सागर के कुछ अलग-अलग हिस्से पर विवाद है। चीन अपनी एंटी एरिया एक्सेस डिनाइल सैन्य रणनीतिक के तहत पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व विरोध करता रहा है। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि पीएलए अपने आप ही निरंकुश तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है। वह अपने हाईकमान सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जिसका प्रमुख और कोई नहीं स्वयं पार्टी महासचिव और चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग हैं, से मिले आदेशों का पालन भर कर रही है। इसकी निगरानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18 वीं कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी कर रही है। इसलिए जब राष्ट्रपति कहते हैं कि चीन अपने â€˜मुख्य हितोंâ€™ पर कोई रियायत नहीं करेगा दो इसके दायरे में भू-भाग के उसके दावे और हालिया सभी सैन्य दखलअंदाजी और रणनीतिक-सैन्य क्षमता का विकास सभी आ जाते हैं। अपने दावे के समर्थन के लिए चीनी नेतृत्व औपनिवेशिक इतिहास और सुरक्षा व भूभाग की अखंडता से जुड़ी मौजूदा वजहों को अपने रुख और कार्रवाई को न्यायोचित ठहरता है। यह सच है कि भारत और चीन, दोनों का सर्वोच्च नेतृत्व द्विपक्षीय संबंध सुधारने में बड़ा श्रम और समय लगाया है। 67 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार, जो 2012 की आर्थिक मंदी के बावजूद जारी रहा, इसका सबसे बड़ा निदर्शन है। दोनों देशों के शीर्ष स्तर पर आवाजाही बनी ही हुई है। नेता और अफसर बहुपक्षीय मसलों पर एक दूसरे से लगातार संवाद बनाये रहते हैं। ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) जैसा मंच खड़ा करने में भी उनकी कोशिश और सहयोग की महत्ती भूमिका रही है। एक नई वैश्विक व्यवस्था और गंभीर वैश्विक मामलों के प्रति विकासशील देशों के साझा दृष्टिकोण हैं जो एक निर्णायककारी भूमिका अदा करेंगे। लिहाजा, कोई भी ऐसी कड़ी मेहनत को नकारने और विवाद तथा सीमा पर खतरों को लेकर अनजान नहीं है। ठीक इसी तरह, भारत में शायद ही कोई होगा जो "हिन्दी-चीनी भाई-भाई" की वेदी पर अपने भूभाग का बलिदान कर देगा।

भारत को जो करना चाहिए

अत: यहां प्रस्ताव किया जा रहा है कि भारत वह रणनीतिक उपाय करे जो अक्साई चीन से लगी सीमा पर उसके हितों को सुरक्षित करेगा, क्षेत्र का विकास करे और चीन के साथ सैन्य टकराव को भरसक टाले। पहला, भारत को सीमांत क्षेत्रों में अपनी तकनीकी खुफिया क्षमता को बढ़ाना है ताकि वह उस पार होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रख सके। यह वहां कैमरा स्थापित करने से बेहतर होगा, जिसे उठा लिये जाने का खतरा है। दूसरे, विवादग्रस्त क्षेत्र में भारत को सुरक्षा बलों की मौजूदगी और बढ़ाने की जरूरत है ताकि पर्याप्त संख्या बल के साथ हमारी मजबूत जवाब तैयारी का निदर्शन हो सके। तीसरा भारत को अपनी बेहतर सुरक्षा व शासन के लिए बुनियादी ढांचे को लगातार बेहतर बनाने का दायित्व

निभाना होगा। चौथा, बुनियादी ढांचे के क्रमबद्ध विकास के साथ केंद्र सरकार और "एलएएचडीसी" को त्वरित गति से शासन बेहतर करने व उसके निष्पादन के अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर देना होगा। लोगों को सुरक्षित ढंग से कहीं भी बसने, ऐतिहासिक व प्राकृतिक रूप से सुंदर स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पांचवां, चीन से सीमा पार के मुद्दे के समाधान के लिए परस्पर आदान- प्रदान और मोलभाव आदि सभी कुछ किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि चीन की तरफ से पीएलए को सीमा पर पूरा अधिकार है जबकि भारत की तरफ से इसमें केंद्र, राज्य, सेना, अर्धसैनिक बल आदि शामिल हैं। लिहाजा भारत को सीमा की सुरक्षा के मुद्दे पर कई एजेंसियों के शामिल होने का फायदा उठाना चाहिए। भारत-चीन सीमा विवाद का सावधानीपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए अन्यथा हम पीएलए के हाथ मजबूत कर देंगे और इस मुद्दे का सैन्यकरण हो जाएगा। इस दौरान चीन का धैर्यवान नहीं होना भारत के पक्ष में जा सकता है। अंतिम रूप से भारत को दोनों पक्षों को स्वीकार्य सीमा समझौता करना चाहिए, ताकि भारत को शासन बेहतर करने व क्षेत्र में सामरिक संतुलन कायम रखने में मदद मिले। यह भारत की नीति व कूटनीति में परिलक्षित होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र भारतीय प्रेस की प्रतिष्ठा का भी समुचित ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लिहाजा, चीन को यह संदेश देने में भारत को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि वह सीमा पार से भेजे गए उसके किसी संदेश का माकूल जवाब दे सकता है-चाहे वह चीनी प्रधानमंत्री ली ख-छियांग के करमर्दन का हो या पीएलए की कारगुजारियों का। भारत को सही ट्रैक पर रहना चाहिए और यह करने के लिए उस क्षेत्र में अपनी सैन्य व सामाजिक-आर्थिक बुनियाद को मजबूत करना चाहिए। आज केवल खुद की आर्थिक और सैन्य क्षमता ही देश की सम्प्रभुता की गारंटी हो सकती है।

****